



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 328] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 8, 1980/आषाढ़ 17, 1902

No. 328] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 8, 1980/ASADHA 17, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आवेश

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 1980

कां०आ० 537(अ)/18क/ओ०वि०वि०क०अ/80.—केंद्रीय सरकार ने, उद्योग [विकास और  
विनियमन] अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के अधीन जारी किए गए  
भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के अधिसूचित आदेश सं० कां०आ०  
218(अ)/18क/ओ०वि०वि०क०अ/78 तारीख 29 मार्च, 1978 द्वारा घेम्ट बंगाल फारेस्ट डेवलप-  
मेंन्ट कारपोरेशन लिमिटेड को कलकत्ता स्थित मैसर्स आलोक उद्योग यन्त्रागति और प्लाईवुड  
लिमिटेड का (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) उसमें विनिविष्ट  
अपधि के लिए प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 183 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाययुक्त अनुसूची में ऐसे अपवाद, निर्वन्धन और सीमाएं बिलिखित करती हैं, जिनके अधीन रहते हुए कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), उक्त औद्योगिक उपक्रम की उसी शीति में लागू होता रहेगा जैसे कि वह धारा 184 के अधीन अधि-सूचित घाटन के जारी किए जाने से पूर्व उसे लागू होता था।

#### अनुसूची

कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्ध	वे अपवाद, निर्वन्धन और सीमाएं जिनके अधीन रहते हुए खंड (1) में उल्लिखित उपबन्ध उपक्रम को लागू होंगे
1	2
धारा 166	कम्पनी की धारा 166 के अनुसार साधारण वार्षिक प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है तथापि तुलन-पत्र और लाभ और हानि लेखा यथावत तैयार किया जाएगा और इसकी लेखा परीक्षा बिलिखित समय के भीतर की जाएगी और अन्य कानूनी विवरणियों के साथ कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा।
धारा 224	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को इस शर्त के अधीन रहते हुए लागू नहीं होंगे कि लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी

[फा० सं० 2/25/74/सी०यू०एस०]

बी० राय, संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF INDUSTRY (Deptt. of Industrial Development)

#### ORDER

New Delhi, the 8th July, 1980

S.O. 537(E)/18E/IDRA/80.—Whereas by the notified Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 213(E)/18A/IDRA/73, dated the 29th March, 1978, issued under Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government has authorised the West Bengal Fores Development Corporation Limited to take over the management of the Industrial undertaking known as M/s. Alok Udyog Vansapati and Plywood Limited located at Calcutta (hereinafter referred to as the said Industrial undertaking) for the period specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2 of section 18E of the said Act, the Central Government, hereby specifies, in the Schedule annexed hereto, the exceptions, restrictions and limitations, subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the said industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the said notified Order under section 18A.

## SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the undertaking.
1	2
Section 166 . . . . .	The company need not hold the annual general meeting in accordance with section 166. However, the balance sheet and profit and loss account shall be prepared and audited as usual within the prescribed time and will be filed with the Registrar of Companies along with other statutory returns.
Section 224 . . . . .	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking subject to the condition that the Auditors shall be appointed by the Government of India.

[F. No. 2/25/74-CUS]

B. ROY, Jt. Secy.

